

भारत सरकार  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3368  
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

**चैम्पियन एमएसएमई**

3368. श्री इटेला राजेंदर:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चैम्पियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें राज्यों की क्या भूमिका है;
- (ख) चैम्पियन एसएमई के सृजन करने और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में मान्यता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) भविष्य के चैम्पियन बनाने और चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए दस हजार करोड़ रुपए के समर्पित एसएमई विकास कोष की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) सूक्ष्म उद्यमों को सहायता जारी रखने और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच बनाए रखने के लिए दो हजार करोड़ रुपये की राशि से गठित आत्मनिर्भर भारत निधि को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और
- (च) कार्यान्वित की गई योजनाओं, वर्तमान स्थिति और उनके अंतर्गत स्वीकृत/जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री  
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (च): केंद्रीय बजट 2026-27 में, सरकार ने चुनिंदा मानदंडों के आधार पर इकटिटी समर्थन के माध्यम से उद्यमों को प्रोत्साहित करते हुए, भविष्य के चैम्पियन निर्मित करने के लिए एक समर्पित 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास कोष की घोषणा की है। भारत के लघु व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्ट-अप्स की ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने कूरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख रुपये की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह से हटाने की भी घोषणा की है। इन घोषणाओं के तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।

\*\*\*